नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 054
दि. 23.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बारिश के मौसम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी वासियों के नाम 'पाती' में किए 5 आग्रह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले प्रदेश वासियों के नाम 'योगी की पाती' लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बारिश के मौसम से जुड़े कई संदेश दिए हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊः बारिश का मौसम आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को पाती (चिट्ठी) लिखी है। उन्होंने वर्षा ऋतु से पहले राज्य के लोगों से 5 आग्रह किए हैं। उन्होंने पौधों का रोपण करने, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, जल संचयन करने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, बरसात में स्वच्छता बनाए रखकर संक्रामक रोगों से बचाव करने और बारिश के दिनों में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से बचाव के लिए सावधानियां बरतने का संदेश दिया है।

जीवन का नया संदेश देता है हर प्राकृतिक बदलाव

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर शेयर की गई पोस्ट 'योगी की पाती' में कहा है कि, 'प्रकृति का प्रत्येक परिवर्तन जीवन का नया संदेश लेकर आता है। वर्षा ऋतु नवसृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे अन्नदाताओं का श्रम ही प्रदेश और देश की खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा

आधार है। वर्षा की पहली फुहार की सुगंध हमारे अन्नदाताओं के जीवन में नव-ऊर्जा का सृजन करेगी। वर्षा ऋतु के साथ चातुर्मास का पावन काल भी आरंभ होता है। यह काल हमें प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है।'

उन्होंने लिखा है, 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः अर्थात यह भूमि हमारी माता है और हम इस भूमि के पुत्र हैं। अतः यह समय प्रकृति का स्वागत करने के साथ-साथ धरती मां के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का भी है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से पांच आग्रह करना चाहता हूं।' उन्होंने राज्य के लोगों से पांच आग्रह किए हैं।

पहला आग्रह

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत प्रत्येक परिवार कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसके संरक्षण का संकल्प ले।

दूसरा आग्रह

जल है तो कल है, इस भाव के साथ जनभागीदारी के माध्यम से तालाबों, पोखरों, अमृत सरोवरों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता के साथ-साथ घर, विद्यालय, ग्राम पंचायत और संस्थानों में वर्षा जल संचयन को जन अभियान बनाएं।

तीसरा आग्रह

प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा दें। इससे हमारा परिवार, समाज और प्रदेश स्वस्थ होगा तथा समृद्ध एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

चौथा आग्रह

स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए बरसात के मौसम में स्वच्छता बनाए रखें और जलजनित एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु सावधानी बरतें।

पांचवां आग्रह

आसपास जल जमाव न होने दें, कूड़े का ढेर न लगने दें। नालियां प्लास्टिक से जाम न हों, इसका विशेष ध्यान रखें।

प्राकृतिक घटनाओं से बचाव का संदेश

मुख्यमंत्री योगी ने बारिश के मौसम में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से बचने के लिए सावधानियां बरतने का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि, 'वर्षा के समय आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, अतः उस समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पेड़ों के नीचे खड़े न हों। कई बार अतिवृष्टि के कारण नदियों एवं जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। अतः इस दौरान नदियों एवं जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें। सरकार ने इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, फिर भी आप सभी सतर्क एवं सजग रहें। आप सभी का सहयोग ही हमारे प्रयासों को सार्थक करेगा।'

कोचिंग सेंटर में आग, 18 छात्रों की मौत, मौके पर डिप्टी सीएम; योगी अलीगढ़ से लौटे

(जीएनएस)।

लखनऊ। अलीगंज के सेक्टर डी में सोमवार दोपहर निजी कोचिंग सेंटर में आग लग गई। कुछ ही देर में लपटें विकराल हो गई। आसपास के लोगों ने सूचना दमकल को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए हैं। इस हादसे में 18 छात्रों की मौत हो गई और कई झुलस गए हैं।

आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आसपास के लोगों का कहना है कि कुछ लोग अंदर फंसे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से घटना को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है।

कई विद्यार्थियों ने नीचे कूद कर जान बचाई। कुछ को गंभीर रूप से चोटें आयी हैं। जिस इमारत में आग लगी वहां पर पहले दो तल पर पेट शाप और गेमिंग जोन था और तीसरे तल पर कोचिंग और लाइब्रेरी थी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने व घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा किक हमें पता चला है

कि अभी सबसे ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अंदर जाने के लिए पहली मंजिल की एक दीवार तोड़ी है। वहां बहुत ज्यादा धुआं है। हर कमरे की तलाशी ली जा रही है। हमारी प्राथमिकता सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना है। प्रशासन और मेडिकल टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं और हमने डॉक्टरों को भी यहां बुलाया है। जिन बच्चों को तुरंत प्राथमिक उपचार की जरूरत हो सकती है, उन्हें यहीं पर इलाज देने का इंतजाम भी किया गया है।

स्थानीय लोग बोले- नीचे कूद रहे थे छात्र

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि घटना के वक्त कई बच्चे

अंदर थे। आग लगी तो वह नीचे कूदने लगे। घटना से जुड़े कई फोटो और वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए हैं।

मौके पर डीएम विशाख, एडीसीपी उत्तरी टि्वंकल जैन समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियां और एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से कर्मचारी रेस्क्यू में जुटे हैं। घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

आसपास की इमारतों को कराया गया खाली

एहतियात के तौर पर पुलिस ने आसपास की इमारतों को खाली कराया है। रेस्क्यू आपरेशन के लिए यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बड़ी संख्या में पुलिस, प्रशासन और दमकल के कर्मी मौके पर पहुंचे हैं।

अलीगढ़ से लखनऊ लौट रहे सीएम योगी

लखनई में हिए अग्निकांड के बाद सीएम अलीगढ़ से लखनऊ वापस लौट रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि में अलीगढ़ में रहूं। मगर मुझे अभी जनाकारी हुई है कि लखनऊ में एक आग की घटना हुई है। बच्चे चपेट मे आएं हैं। मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी उनके प्रति चिंता है। परिवारों के प्रति संवेदना है।

उन्होंने कहा कि मैंने प्रमुख सचिव ग्रह को जांच के आदेश दिए हैं। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मेरी लिए वह महत्वपूर्ण है। मुझे यहां से जल्दी जाना होगा। वह घटना महत्वर्ण है। लखनऊ की घटना में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी स्थिगित कर दी। केवल लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की।

'ये बेहद दुखद घटना, कारणों की ईमानदारी से जांच हो', लखनऊ अग्निकांड पर बोले अखिलेश यादव

यूपी के पूर्व सीएमः एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरानिया में सोमवार (22 जून) को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हो गए. वहीं इस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया है. अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, "लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि.

ममता को हटाकर अरूप रॉय बने टीएमसी के नए चेयरमैन, अभिषेक भी महासचिव पद से बाहर

(जीएनएस)।

कोलकाता। बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार के बाद पार्टी में जारी बगावत सोमवार को नए मोड़ पर पहुंच गई। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने दावा किया कि उसने पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यसमिति गठित कर दी है।

इस नई समिति में हावड़ा मध्य के विधायक अरूप राय को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पद से हटा दिया गया है। वहीं, अभिषेक बनर्जी को भी राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाकर नई नियुक्तियों की घोषणा की गई।

बजट सत्र समाप्त होने के बाद न्यू टाउन के एक होटल में बागी विधायकों की बैठक हुई। गुट का दावा है कि इसमें 60 विधायक और कोलकाता के लगभग 70 पूर्व पार्षद शामिल हुए। बैठक में 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यसमिति के गठन की घोषणा की गई।

बागी नेताओं ने तृणमूल के

संविधान की धारा-20 का हवाला देते हुए कहा कि हर तीन वर्ष में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन 2022 के बाद ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। इसी आधार पर पुरानी कार्यसमिति को भंग कर नई समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

नई समिति में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास, विधायक फिरहाद हकीम और रथीन घोष को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव के रूप में ऋतब्रत बनर्जी के साथ जावेद खान, संदीपन साहा और सबीना यासमिन को जिम्मेदारी दी गई है।

अखरुज्जमान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोमवार की बैठक में बागी गुट ने दावा किया कि वही 'असल तृणमूल' है। बैठक में चंद्रिमा भट्टाचार्य के पुत्र और पूर्व पार्षद सौरभ बसु की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही।

हालांकि, ममता खेमे ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने कहा कि तृणमूल और ममता बनर्जी एक-दूसरे के पर्याय हैं।

अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर प्रतिबंध हटायाःअगले 60 दिन भारत भी खरीद सकता है, ईरान में फिर तैनात होंगे यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर

(जीएनएस)।

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन, अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगी पाबंदियों में 60 दिन की ढील दे दी है। यह फैसला स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, डिलीवरी और बिक्री के लिए अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है। यह छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इससे भारत समेत कई देश फिर से ईरानी तेल खरीद सकेंगे।

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में बिना रोक-टोक आवाजाही बनाए रखने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही ईरान वठ की परमाणु एजेंसी क्अएअ के इंस्पेक्टर्स को दोबारा देश में काम करने की मंजूरी देने पर भी सहमति जताई है।

अमेरिका और ईरान के बीच आज स्विट्जरलैंड में लगातार दूसरे दिन भी बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका की कोशिश ईरान के साथ स्थायी समझौते तक पहुंचने की है

और अब तक की बातचीत में अच्छी तरह आगे बढ़ी है।

पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्सङ्घ

1. ईरान-अमेरिका के बीच बातचीतः दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड में करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों देश 60 दिन के युद्धविराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

2. वेंस बोले- मिलकर शांति के लिए काम करेंगेः अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। उनके मुताबिक, दोनों देश मिलकर शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं और ट्रम्प अगले 10 साल में पश्चिम एशिया की तस्वीर बदलना चाहते हैं।

3. ट्रम्प की ईरान को धमकीः ट्रम्प ने कहा कि ईरान लेबनान में अपने समर्थक हिजबुल्लाह को तुरंत रोके। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर अमेरिका पिछले हफ्ते से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा।

4. लेबनान में मौतों का आंकड़ा 4,100 के पारः लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 2 मार्च से अब तक 4,106 लोगों की मौत और 12,153 लोग घायल हुए हैं। वहीं, इजराइली सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है।

5. ईरान का दावा- कतर में फंसे 6 अरब डॉलर मिलेंगेः ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए शुरूआती समझौते के तहत कतर में जमा ईरान के 6 अरब डॉलर वापस मिलेंगे।

ट्रंप की धमकी के बाद बैठक से ईरान ने किया वॉक आउट,अमेरिका-ईरान की पहली बैठक बेनतीजा

स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता गंभीर संकट में घिर गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर फिर से हमले की कड़ी चेतावनी के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने आमाने-सामने हो रही इस मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही, ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज को दोबारा बंद करने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

यह वार्ता पिछले हफ्ते दोनों देशों द्वारा अंतरिम शांति समझौते को लागू करने से संबंधित थी जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है।

अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या जाने का किया ऐलान, बोले- राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी दुखी

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 26 जून को अयोध्या जाकर श्रीराम मंदिर में दर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह फैसला अयोध्या के राम मंदिर में सामने आए कथित चढ़ावा और चंदा चोरी विवाद के बाद लिया है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या जाकर श्री राम मंदिर के दर्शन करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी है। उन्होंने लिखा ' अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिये श्री राम मंदिर जाऊंगा'।

बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर

में दान और चढ़ावे की गिनती में कथित गड़बड़ी और हेराफेरी का मामला गरमाता जा रहा है। जून में सामने आए इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी (SIT) का गठन किया और मंदिर के 40 कर्मचारियों को दान की गिनती से हटा दिया गया है।

वहीं अरविंद केजरीवाल के पोस्ट का जवाब देते हुए भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने लिखा "शुक्रवार को जाएंगे? जुमे की नमाज के पहले या उसके बाद?" कपिल मिश्रा के इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो सकती है। आम आदमी पार्टी पलटवार कर सकती है।

अलग-अलग तरफ से आरोपों के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है जो दान और आभूषणों के रखरखाव में शामिल संदिग्ध कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने घोटालों के दावों को खारिज किया है। ट्रस्ट ने अफवाहों को नकारते हुए खुद स्वतंत्र जांच का समर्थन किया है।

अलीगढ़ में सीएम योगी का एक्शन मोड, विश्वविद्यालय पहुंचते ही अफसरों की क्लास शुरू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विवि पहुंचने के बाद सीधे कुलपति कक्ष में पहुंचे, जहां

जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाईलेवल समीक्षा बैठक शुरू हुई। बैठक में विकास परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों की चार्चा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की जमीनी स्थिति, समयबद्ध क्रियान्वयन और लंबित कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निवेश, सड़क परियोजनाओं, बिजली व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर पीएम मोदी-राहुल गांधी ने जताया दुख, प्रधानमंत्री ने किया मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए कोचिंग अग्निकांड मामले में पीएम, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह समेत कई राजनेताओं ने दुख जताया है। साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपये के मुआवजे का भी ऐलान किया है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण आग लग गई। कोचिंग सेंटर से अब तक 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इस भयावह अग्निकांड को लेकर पीएम मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 'उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारी हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।' इसके साथ ही पीएम मोदी ने ढटठफ्क्र से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भी ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

लखनऊ हादसे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

राहुल गांधी ने जताया दुख

राहुल गांधी ने भी इस भीषण अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।'

राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया

रक्षामंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है, जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber · Jio Tv + · Jio Fiber · Daily Hunt · ebaba Tv · Dish Plus

DTH live OTT · Rock TV · Airtel · Amezone Fire · Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर हादसा: अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार नहर में गिरी, पांच घायल

(जीएनएस)।

लखीमपुर। लखीमपुर-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कस्बा ओयल के बेहजम तिराहे के निकट स्थित फौजी धर्मकांटा के पास से गुजर रही शारदा सहायक नहर की माइनर में एक वैगनआर कार अनियंत्रित होकर जा गिरी।

हादसे में कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब दो बजे लखनऊ की ओर से आ रही वैगनआर कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बनी छोटी नहर में जा घुसी। कार के नहर में गिरते ही तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर आसपास झुग्गियों में रह रहे लोग मौके पर दौड़ पड़े। उसी दौरान क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई।

स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने संयुक्त रूप से राहत कार्य शुरू किया और कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया।

हादसे में घायल लोगों की पहचान शहर के मोहल्ला शांतिनगर गढ़ी रोड निवासी आशुतोष नंदन दीक्षित उर्फ रिंकू (52) पुत्र रविशंकर, उनकी पत्नी रेनू, 15 वर्षीय पुत्र शिवांश, तथा मोहल्ले के ही अधिवक्ता रामप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी सरिता के रूप में हुई है।

बताया गया कि सभी लोग अयोध्या दर्शन के लिए गए थे और रविवार रात वापस लखीमपुर लौट रहे थे। कार को आशुतोष नंदन दीक्षित चला रहे थे। जैसे ही वाहन ओयल क्षेत्र में पहुंचा, अचानक नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे नहर में जा गिरी।

प्रारंभिक तौर पर चालक को झपकी आने अथवा वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।

दुर्घटनाग्रस्त कार को नहर से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हादसे के बाद कुछ समय तक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

पुलिस का कहना है कि सभी घायलों का इलाज चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में सहयोग करने वाले ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों की सराहना की, जिनकी तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

न्यूमरोलॉजी पर आधारित प्रणिता घोड़े की अनूठी कला प्रदर्शनी 'ग्रह पूर्ति यन्त्रम' 2 जुलाई से मुंबई में

मुंबई, 22 जून। न्यूमरोलॉजी पर आधारित चित्रकला की नई विधा की शुरूआत करने वाली मशहूर चित्रकार सुश्री प्रणिता घोड़े की अनूठी कला प्रदर्शनी "ग्रह पूर्ति यन्त्रम" आगामी 2 जुलाई, 2026 से मुंबई में आयोजित की जा रही है।

यह जानकारी देते हुए मुंबई महानगर की प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था "आकृति आर्ट फाउंडेशन" के डायरेक्टर मनमोहन जायसवाल ने बताया कि यह अनूठी कला प्रदर्शनी मुंबई के भूला भाई देसाई रोड स्थित सिमरोजा आर्ट गैलरी में में 2 जुलाई से 5 जुलाई, 2026 तक सभी दर्शकों के निःशुल्क अवलोकनार्थ खुली रहेगी। 2 जुलाई, 2026 को इस कला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध साहित्यकार, वरिष्ठ समाज सेविका और लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मंजू लोढ़ा शामिल होंगी। साथ ही अन्य प्रमुख अतिथियों के रूप में मशहूर भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉ. सोमा घोष, वरिष्ठ उद्योगपति अजोयकांत रुइया, समाजसेविका मालती जैन, किशोर जैन खाबिआ और देवेंद्र गुरुजी के अलावा महानगर के प्रबुद्ध कलाप्रेमी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सुश्री प्रणिता पिछले 15 वर्षों से न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत भाग्यांक और मूलांक पर आधारित पेंटिंग करती हैं। इस बारे में सुश्री प्रणिता ने बताया कि पिछले 15 वर्षों के अध्ययन, अनुभव और निरंतर शोध के आधार पर उन्होंने

जन्मतिथि के अंकों पर आधारित व्यक्तिगत ह्यग्रहपूर्ति यंत्रह्ण की संकल्पना विकसित की है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की जन्मतिथि के अंकों के संतुलन, उनके गणितीय सम्बंधों का अध्ययन तथा उन्हें कलात्मक रूप में कैनवास पर प्रस्तुत करना शामिल है। उनका मानना है कि यह कला, न्यूमरोलॉजी और रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक अनूठा संगम है।उनका कहना है कि यह विधा, कला के क्षेत्र में उनकी गहन खोज का निष्कर्ष है। उन्होंने कहा कि उनकी कला न केवल एक विजुअल ब्यूटी है, बल्कि यह जीवन में अनुकूलता, सुख-शांति और समृद्धि भी लाती है। उन्होंने बताया कि ग्रहपूर्ति यंत्र अथवा शुभ-अशुभ पूरी तरह व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास का विषय है। पूरी दुनिया में लोशो ग्रिड को विशेष महत्व दिया जाता है। जन्म तिथि के अनुसार जिन अंकों की आवश्यकता होती है, उनके संतुलन के लिए महंगे रत्न, विशेष रंग, पेड़ों की जड़ें तथा विभिन्न प्रकार के उपाय और रेमेडीज बताये जाते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों में लोशो ग्रिड के मूल अंकों को बदला नहीं जाता। हिंदू धर्म में श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र आदि में अंकों की स्थिति सुनिश्चित मानी जाती है, जिन्हें ग्रहों की शुभ स्थिति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन्हें घर में स्थापित करने से सकारात्मक आभामंडल निर्मित होता है, जो व्यक्ति के जीवन पर लाभकारी प्रभाव डालता है तथा मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। उन्होंने बताया कि ग्रहों की राशि में जैसे अनेक अंक अंतर्निहित होते हैं, उसी प्रकार अंतरिक्ष में अनेक ग्रह-गोल विद्यमान हैं। इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री जयंत नारळीकर ने अपने गुरुत्वीय स्थिरांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा घिरे हुए अंतरिक्ष और उसके गुरुत्वाकर्षण के बीच का अनुपात सदैव 6.6 के स्थिरांक पर आधारित माना जाता है। इसी प्रकार ग्रहपूर्ति यंत्र में भी आड़ी, ऊर्ध्व तथा तिरछी दिशाओं में अंकों की गणना स्थिर बनी रहती है और वही हमारा भाग्यांक माना जाता है। उन्होंने कहा कि गुरुत्वीय स्थिरांक सिद्धांत पर आधारित 16 घरों वाला यह भाग्यांक यंत्र जन्मतिथि के अनुसार आवश्यक अंकों का सही संतुलन और नियोजन करता है। इसमें मूल भाग्यांक को बदला नहीं जाता।इसकी विशेषता यह है कि मूल भाग्यांक वही बना रहता है, इसलिए अलग-अलग रेमेडीज की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाती है।

पंजाब कैबिनेट ने स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म लागू करने को स्वीकृति दी

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने तथा प्रशासनिक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी, औद्योगिक रियायतों संबंधी दिशानिदेर्शों में संशोधन किया, स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म लागू करने की स्वीकृति दी तथा जिला होशियारपुर के अंतर्गत आने वाले दसूहा उपमंडल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) और सहायक स्टाफ के पद सृजित करने को मंजूरी दी।

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाम

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस में की जाने वाली अनावश्यक और अनुचित बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026' को लाने को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016' में संशोधन करके लाया गया है।

इस कदम का उद्देश्य फीस वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण रखना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को मनमानी फीस बढ़ोतरी से सुरक्षा प्रदान करना, फीसों के ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा उनके हितों की रक्षा करना है। इन संशोधनों के तहत फीस, फीस वृद्धि और कुल फीस वृद्धि की परिभाषाओं को अधिक स्पष्ट बनाया गया है। साथ ही, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा वार्षिक फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है। 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के लिए संबंधित नियामक संस्था की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी संबंधी दिशानिदेर्शों में संशोधन

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत कैपिटल सब्सिडी एवं निवेश प्रोत्साहनों के वितरण के लिए 13 नवंबर 2019 के दिशानिदेर्शों में संशोधन को भी मंजूरी दी।इन संशोधनों का उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को सरल और सुचारु बनाना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना तथा पात्र औद्योगिक इकाइयों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, दिशानिदेर्शों की धारा 1.1 और 1.2 में छूट मिलने के बाद पात्र बनने वाली औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर कैपिटल सब्सिडी जारी की जाएगी।

पंजाब में स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म लागू करने को मंजूरी

राज्य के विभिन्न विभागों के अनेक डेटाबेसों को आपस में जोड़ने, किसी भी दोहराव को समाप्त करने और मौजूदा प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब में स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म (एसडीआईपी) लागू करने को मंजूरी दी है।परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन-स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी।इस संचालन समिति में पंजाब के मुख्य सचिव चेयरपर्सन होंगे, प्रशासनिक सचिव (गुड गवर्नेंस) मैंबर कनवीनर होंगे तथा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

दसूहा उपमंडल के लिए एडीसी (जनरल) और सहायक स्टाफ के पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने जिला होशियारपुर के अंतर्गत आने वाले दसूहा उपमंडल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) तथा अन्य सहायक स्टाफ के पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से क्षेत्र के उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्यों, अनुमतियों, राजस्व मामलों तथा जन शिकायतों के निपटारे के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी तथा जनहित से जुड़े मामलों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा। इसलिए जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला होशियारपुर के अंतर्गत दसूहा उपमंडल में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) सहित सहायक स्टाफ के कुल पांच पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

देवरिया में सीएम योगी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज, डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

(जीएनएस)।

देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सोमवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरांव पहुंची और प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 26 जून को प्रस्तावित है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

अधिकारियों ने पकड़ी-बरांव मार्ग के समीप प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग,

मंच व्यवस्था, जनसभा स्थल, हेलिपैड और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान डीएम मधुसूदन हुल्गी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था तथा आमजन की सुविधा से जुड़े सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को संवेदनशील बिंदुओं की पहचान कर सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान राजस्व, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, विद्युत, पंचायत एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

लखनऊ अग्निकांड पर प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल, बोलीं- 'मुआवजा, जांच और फिर सब भूल जाते हैं'

लखनऊ अग्निकांड की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा बीच में ही छोड़कर राज्य की राजधानी लौट आए हैं.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं हैं. लखनऊ अग्निकांड को लेकर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हुए इस घटना पर दुख जताया है.

पूर्व सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया,"एक और दिन, एक और

आग. वही कहानी दोहराई जाती है - मुआवजा, जांच और फिर सब भूल जाते हैं. मैंने पिछले हफ़्ते मालवीय नगर में लगी आग के बाद इस बारे में बात की थी."

इस घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन विभाग को दोपहर करीब तीन बजे अलीगंज थाना क्षेत्र के उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक कोचिंग संस्थान की इमारत में आग लगने की सूचना मिली थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद कई लोग इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि कुछ अन्य लोगों के अंदर फंस गए.

लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट

KGMU के ट्रॉमा सेंटर के उटर डॉ. प्रेम राज सिंह कहते हैं, "अस्पताल में कुल 21 लोगों को लाया गया, जिनमें से छह की हालत स्थिर है. एक बच्चा जो ऊपरी मंजिल से कूदा था, उसकी कमर में चोट आई है और वह भी स्थिर है. बाकी 15 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था. हम जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं और शवों को मुर्दाघर भेज रहे हैं. अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और दवाओं या बेड की कोई कमी नहीं है."

गुजरात से लेकर लखनऊ तक... गेमिंग जोन में जल्दी क्यों लगती है आग? जान लें वजह

(जीएनएस)। हाल ही में लखनऊ के अलीगंज इलाके के एक गेमिंग जोन में आग लग गई. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर गेमिंग जोन में इतनी जल्दी आग क्यों लग जाती है.

(जीएनएस)।सोमवार को लखनऊ के अलीगंज इलाके के पूर्णिया में एक गेमिंग जोन में आग लगने की घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक आग के लपटें और घना धुआं तेजी से पूरी इमारत में फैलता चला गया. इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. ऐसा ही एक हादसा गुजरात के राजकोट में भी हुआ था. आइए जानते हैं कि आखिर गेमिंग जोन में जल्दी क्यों लग जाती है आग.

गेमिंग जोन में आग लगने का खतरा ज्यादा क्यों होता है?

गेमिंग जोन को लाइटिंग इफेक्ट, साउंड प्रूफिंग, थीम आधारित इंटीरियर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए शानदार अनुभव के लिए डिजाइन किया जाता है. अगर सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो इन आकर्षणों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजें और सिस्टम जानलेवा साबित हो सकते हैं. पिछली घटनाओं की जांच में बार-बार उन्हीं खतरों का पता चला है जिनकी वजह से आग काफी तेजी से फैलती है.

आसानी से आग पकड़ने वाले इंटीरियर

आग की तेजी से फैलने की सबसे बड़ी वजह है यह है कि गेमिंग जोन में कुछ ऐसी चीजें रखी होती हैं जो तेजी से आग पकड़ सकती हैं. गेमिंग जोन में आमतौर पर थमोकील, सिंथेटिक कपड़े , प्लास्टिक की सजावट, फाइबर पैनल और साउंड प्रूफिंग सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह की चीजें कुछ ही सेकंड के अंदर आग पकड़ सकती हैं और काफी जहरीला धुआं भी पैदा कर सकती हैं.

बिजली का ज्यादा लोड

गेमिंग सुविधाओं में दर्जनों हाई पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है. यह सभी एक साथ चलते हैं. गेमिंग कंसोल, कंप्यूटर, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, एलईडी डिस्प्ले, एयर कंडीशनर, लाइटनिंग सिस्टम और साउंड उपकरण बिजली के नेटवर्क पर काफी ज्यादा दबाव डालते हैं. अगर वायरिंग पुरानी है और ठीक से नहीं लगाई गई या फिर उस पर काफी ज्यादा लोड है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है. बिजली की चिंगारी से आसपास मौजूद आसानी से आग पकड़ने वाली चीजों में तुरंत आग लग सकती है.

डीजल और ईंधन का भंडारण

कई गेमिंग जोन बिना रुकावट बिजली सप्लाई के लिए डीजल जनरेटर पर निर्भर होते हैं. ऐसा कहा जाता है कि गेमिंग सुविधाओं के अंदर या फिर आस-पास बड़ी मात्रा में ईंधन रखने से आग लगने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है.

इसी के साथ वेल्डिंग, कोटिंग या फिर मरम्मत के काम से अक्सर चिंगारी निकलती रहती है. अगर ऐसे काम फोम शीट, कपड़े, प्लास्टिक के ढांचे या फिर ईंधन रखने की जगह के पास किए जाते हैं तो तुरंत आग लग सकती है.

लखनऊ अग्निकांड में मृतकों की सूची, 19 साल से लेकर 30 साल तक के छात्रों ने गंवाई जान

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर को तीन मंजिला एक बिल्डिंग में लगी आग में झुलसकर 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं, सात अन्य घायल हैं, जिनका इलाज केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में एनीमेशन कोचिंग सेंटर चलता है। मरने वालों में ज्यादातर छात्र हैं।

घटना की जानकारी होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस और अलीगढ़ कार्यक्रम रद्द करके लखनऊ लौट आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामले की जांच के सख्त निर्देश दिए। वहीं, अस्पताल में घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना।

अलीगंज अग्निकांड में जान गंवाने वाले 15 लोगों में से 10 की पहचान कर ली गई है। मरने वालों में सागर (27), नीलेश (27), अनामिका (28), श्याम (30), अनुचा (25), सोमालिया (30), शाहजान (19), रुक्मणि (24), आदित्य श्रीवास्तव (23) और अब्दुल रहमान (24) हैं। पोस्टमार्टम हाउस भेजी शव के पहचान के लिए लगातार परिजन पहुंच रहे हैं। अभी कुछ शवों

की पहचान होना बाकी है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के जनसंपर्क अधिकारी के.के. सिंह ने बताया कि इस घटना में बचाव दल द्वारा कुल 22 लोगों को केजीएमयू लाया गया, जिनमें से 15 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि हादसे में सात अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है।

केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने ट्रॉमा सेंटर में बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सूचना मिलने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान की निगरानी की।

बता दें कि आग अलीगंज थाना इलाके में उषा मेहता मार्ग पर स्थित तीन मंजिला वाणिज्यिक इमारत में अपराह्न करीब तीन बजे लगी। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल वाहनों और ह्यहाइड्रोलिक प्लेटफॉर्मह्ण वाली गाड़ी को अभियान पर लगाया गया। पुरनिया बाजार से चंद कदमों की दूरी पर स्थित यह इमारत अलीगंज के पॉश रिहायशी इलाके में है, जहां कोचिंग सेंटर और कैफे जैसी जगहें हैं।

अधिकारियों के अनुसार बचाव अभियान के दौरान आग में फंसे लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। कुछ लोगों को ह्यबॉडी बैगह्ण में लाया गया, जबकि कुछ को कंबल में लपेटा गया था और एम्बुलेंस में ले जाते समय वे बेहोश लग रहे थे। इन लोगों के शवों या घायलों को बगल की इमारत की छत से बाहर निकाला गया।

अयोध्या मंदिर चढ़ावा विवाद में दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई के लिए बलिया से बटुकों ने सीएम को लिखा पत्र

(जीएनएस)।

बलिया। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में बलिया के रेवती क्षेत्र में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम के बटुकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पत्रक भेजा।

कार्यक्रम में बटुक शिवराज पांडेय ने कहा कि भगवान श्रीराम

के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान में कथित चोरी की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों का जल्द पता लगाया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वहीं, बटुक हरिओम पांडेय ने कहा कि राम की नगरी में भगवान राम के नाम पर आने वाले दान में गड़बड़ी होना आस्था को ठेस पहुंचाने वाला विषय है। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द चिह्नित कर कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

अमेरिका- ईंरान युद्धविराम-अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया

लगभग चार महीनों से पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईंरान के बीच हुआ प्रारंभिक समझौता (एमओयू) अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता से पहले ही यह स्पष्ट हो गया है कि समझौते का सबसे संवेदनशील मुद्दा-लेबनान में जारी इज़रायली सैन्य कार्रवाई और उससे जुड़ा युद्धविराम-अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास फिर से उभरता दिखाई दे रहा है।

हाल के दिनों में अमेरिका और ईंरान के बीच एक 14-सूत्रीय समझौते की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस ढांचे का उद्देश्य परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दों और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की सुरक्षा पर आगे की बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना था। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। समझौते के बाद स्विट्जरलैंड में औपचारिक वार्ता और आगे की बातचीत प्रस्तावित थी।

लेकिन घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष फिर भड़क उठा। दोनों पक्षों के बीच हुए युद्धविराम के बावजूद रॉकेट हमले, जवाबी हवाई हमले और सीमा पर सैन्य गतिविधियां जारी रहीं। इन घटनाओं ने उस बुनियादी शर्त को कमजोर कर दिया जिस पर ईंरान ने आगे की वार्ता के लिए सहमति जताई थी।

ईंरानी नेतृत्व का कहना है कि यदि लेबनान में हिंसा नहीं रुकती तो वूटनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाना कठिन होगा। यही कारण है कि वार्ता की समय-सीमा और स्वरूप को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा को पहले स्थगित किया गया था और बाद में नई बैठकों की तैयारी शुरू हुई। दूसरी ओर ईंरानी प्रतिनिधिमंडल ने भी स्पष्ट संकेत दिए कि लेबनान का मुद्दा उनके लिए केवल एक क्षेत्रीय प्रश्न नहीं बल्कि भरोसे की कसौटी है। मौजूदा स्थिति में स्विट्जरलैंड एक बार फिर वैश्विक वूटनीति का वेंद्र बन गया है। ज्यूरिख और अन्य स्विस स्थलों पर अमेरिकी, ईंरानी, पाकिस्तानी और क तरी प्रतिनिधियों की गतिविधियां तेज हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसने पहले भी संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराया था। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा आयाम होर्मुज जलडमरूमध्य भी है। ईंरान की ओर से समय-समय पर जलमार्ग बंद करने की चेतावनी और अमेरिका द्वारा समुद्री यातायात बनाए रखने की प्रतिबद्धता ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान संकट समझौते के पूर्ण विफल होने का संकेत नहीं है। अमेरिका और ईंरान दोनों ही पक्षों ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत दिया है कि वे वार्ता का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि लेबनान में संघर्ष जारी रहने पर किसी भी बड़े समझौते को आगे बढ़ाना बेहद कठिन होगा। वूटनीति तभी सफल हो सकती है जब जमीनी हालात उसमें सहयोग करें। इस समय दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड पर टिकी हैं। वहां होने वाली बातचीत केवल अमेरिका और ईंरान के संबंधों को नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। यदि वार्ता आगे बढ़ती है तो यह क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि नहीं तो अविश्वास, सैन्य तनाव और आर्थिक अनिश्चितता का नया दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल स्थिति नाजुक है, लेकिन वूटनीति का इतिहास बताता है कि सबसे कठिन क्षणों में भी संवाद की संभावना बनी रहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी पक्ष संयम का परिचय देंगे, युद्धविराम का सम्मान करेंगे और टकराव की जगह बातचीत को प्राथमिकता देंगे। अंततः यही आशा है कि शांति, विवेक और सामान्य समझ की जीत होगी तथा क्षेत्र को स्थायी स्थिरता का मार्ग मिलेगा।

योगी सरकार के नौ सालः यूपी में शांति, कानून और विकास का नया युग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नौ वर्षों के शासन में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण आया है। दंगे और माफियाराज खत्म, स्थापित हुई शांति व्यवस्था। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। विकास परियोजनाओं से यूपी बना दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था।

(जीएनएस)।

अब जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन के नौ वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं तो इस बात की मीमांसा भी आवश्यक है कि आखिर जनता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या मायने रखते हैं? वे कौन से कारण हैं जो उन्हें पूर्ववर्ती शासकों से अलग पहचान देते हैं और उनके प्रति विश्वास का धरातल इतना मजबूत कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश के लोगों ने वह समय भी देखा है जब दंगा, दलित उत्पीड़न, सनातन का अपमान और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण इस राज्य की पहचान थे और लोगों को किसी भी मंच पर न्याय की उम्मीद नहीं दिखाई देती थी। लोग अब वर्तमान भी देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बदलती आभा भी, जिसने उनका देश-विदेश सभी जगह सम्मान बढ़ाया है। योगी के प्रति भरोसे की इस धारणा को एक पंक्ति में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में 2017 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ, सुरक्षा, सुशासन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विकास एक ही सूत्र में पिरोए गए और यही उत्तर प्रदेश की नई पहचान के रूप में अब स्थापित है।

एक दृष्टि हम 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश पर भी डालते हैं। उस समय जिस तरह से वोट की राजनीति चरम पर थी और इसके लिए जिस तरह से सांप्रदायिक तुष्टिकरण को तत्कालीन सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल किया, वह एक तरह से राज्य को राजनीतिक गुलामी की ओर ले जाना था। दलितों का उत्पीड़न, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण, विकास की अनदेखी, जनता इन सबके दंश भुगत रही थी लेकिन विरोध का आत्मबल उनसे छीना जा चुका था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2014-2016 के बीच अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे था। दलित उत्पीड़न एक्ट तो इतना निष्प्रभावी था कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। मुजफ्फरनगर का दंगा तो राज्य पर ऐसा कलंक है जो शायद ही कभी धोया जा सके। जाने कितने हिंदुओं का पलायन हुआ और जाने कितने लोगों की जमीनें दबंगों ने हथियाई लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी रही। आक्रोश का लावा कभी न कभी फटता ही है और 2017 में लोगों ने इसे अपने मतों से अभिव्यक्त किया। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 312 सीटें। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल को बहुमत ही नहीं था, अपने अपमान से आहत जनता का विद्रोह था।

जब जनता किसी राजनीतिक दल को इस तरह शिरोधार्य करती है तो सरकार से अपेक्षाएं अत्यंत ही गहरी हो जाती हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती को समझा ही नहीं, आत्मसात भी किया। पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जब तक शासन व्यवस्था अपनी सांस्कृतिक आत्मा से विमुख रहेगी, तब तक वह लोक-कल्याण का वास्तविक मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती। राज्य को आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचना होगा। इस अवधारणा को मुख्यमंत्री योगी ने अपने संकल्प में शामिल किया और 'सुशासन' को केवल एक प्रशासनिक शब्द ही नहीं, युगांतकारी संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया। इसमें उन्होंने वीर सावरकर के विचारों को भी जोड़ा जो यह मानते थे कि शक्ति के बिना शांति की स्थापना असंभव है। योगी ने शक्ति को संकल्प में बदला और माफिया व अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस इसका उदाहरण है। कानून सबके लिए एक है, योगी का यह संदेश पूरे प्रदेश में गूंजा। शपथ लेने के तत्काल बाद अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई ने वोट बैंक की राजनीति को पीछे धकेला तो एंटी-रोमियो स्क्वाड के गठन ने बेटियों को निडर होकर घर से बाहर निकलने का आत्मबल दिया। माफिया के विरुद्ध अभियान तो शायद राज्य के इतिहास में दर्ज किया जाए। माफिया की कमर टूटने का अर्थ था संगठित अपराध का खात्मा। यानि अब राज्य में व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने की जुर्रत कोई नहीं करेगा।

कनाडा से कड़वाहट खत्मः पीएम मोदी-कार्नी की केमिस्ट्री से 2026 तक फ्री ट्रेड डील संभव; खनिजों का खुलेगा खजाना

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बेहतरीन व्यक्तिगत तालमेल से भारत-कनाडा संबंधों का पूरी तरह रीसेट हो गया है। दोनों देशों ने 2026 तक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील पूरी करने और 2030 तक आपसी व्यापार को 50 मिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कनाडा के पास मौजूद भारी मात्रा में यूरेनियम, कोयला और दुर्लभ खनिज भारत की ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में गेम-चेंजर साबित होने जा रहे हैं।

पिछले दो साल से भारत और कनाडा के बीच जो कड़वाहट चल रही थी, वह अब पूरी तरह खत्म होने जा रही है। दोनों देशों के रिश्ते अब एक बेहद मजबूत दौर में पहुंच चुके हैं। इस बड़े कूटनीतिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच की निजी दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच की शानदार केमेस्ट्री ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।

कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस कूटर ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया युग शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि दोनों प्रधानमंत्री अब तक चार बार मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेता फोन पर लगातार बात करते हैं। यही नहीं, दोनों के बीच व्हाट्सएप पर भी संवाद होता है। फ्रांस के एवियन शहर में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों के बीच बेहद खास और सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों ही नेता जमीन पर नतीजे देने में भरोसा रखते हैं। दोनों में काम को जल्द से जल्द पूरा करने की एक जैसी तड़प है। यही वजह है कि पुराना तनाव अब बीते दिनों की बात हो चुका है।

आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश एक नया इतिहास रचने की तैयारी में हैं। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी सेपा (सीईपीए) को साल 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उच्चायुक्त कूटर ने इस डेडलाइन को बेहद व्यावहारिक बताया है। हाल ही में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल देश के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक दल के साथ कनाडा गए थे। उनके साथ कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने भी कमान संभाली। इस यात्रा ने ठंडे पड़े रिश्तों की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल दिया।

दोनों देशों ने अब एक नया और बड़ा लक्ष्य तय किया है। भारत और कनाडा का इरादा साल 2030 तक आपसी व्यापार को तीन गुना करने का है। इसे मौजूदा 17 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर पहुंचाया जाएगा। व्यापारिक जगत भी इस डील को लेकर बहुत उत्साहित है। निवेश की बात करें तो कनाडा ने भारत में लगभग 109 अरब डॉलर का बड़ा निवेश कर रखा है। यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कनाडा के कुल निवेश का 25 फीसदी हिस्सा है। दूसरी तरफ, कनाडा में भारत का निवेश करीब 11 अरब डॉलर है। यह नई डील केवल टैक्स में कटौती तक सीमित नहीं होगी। इसका दायरा बहुत बड़ा और व्यापक होगा।

कनाडा के पास क्लीन एनर्जी और महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) का खजाना है। यह खजाना भारत की औद्योगिक विकास यात्रा के लिए ईंधन का काम करेगा। कनाडा के पास लगभग छह अरब टन धातुकर्म कोयला (मेटालर्जिकल कोल) है। भारत को अपनी भारी इंडस्ट्री के लिए इसकी सख्त जरूरत है। इसके अलावा, भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को आठ गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को भारी मात्रा में यूरेनियम चाहिए। कनाडा दुनिया में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वह भारत के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर बनने को तैयार है।

चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए भी यह दोस्ती बहुत अहम है। चीन से बाहर दुनिया में जितने भी दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ्स) के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें से एक-तिहाई अकेले कनाडा में हैं। कनाडा ने इसके प्रोसेसिंग के लिए सस्केचेवान में उत्तरी अमेरिका का पहला प्लांट भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा, कनाडा अगले एक से दो साल में 50 मिलियन टन प्राकृतिक गैस, एलपीजी और तेल निर्यात करने की क्षमता हासिल कर लेगा। इसके लिए वह अपने पश्चिमी तट पर इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर अपग्रेड कर रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया जैसे राज्यों में खदानों की मंजूरी का समय भी घटाकर सिर्फ एक साल कर दिया गया है।

पीएम मोदी को कनाडा का न्योता

इस पूरी कवायद का सबसे खूबसूरत हिस्सा सुरक्षा के मोर्चे पर आया बदलाव है। पिछले दिनों जो भी तनाव था, उसे पीछे छोड़ते हुए दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने एक मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बना लिया है। दोनों पक्षों के अधिकारी एक-दूसरे की कार्यशैली को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब दोनों तरफ एक ही बात पर सहमति है कि काम में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा पक्ष हैरान या असहज हो जाए।

वैश्विक कूटनीति की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक खास थ्योरी दी थी। इसे 'वेरिएबल ज्योमेट्री' कहा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो देश महाशक्ति नहीं हैं, वे अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए आपस में मजबूत साझेदारियां बनाएं। भारत और कनाडा की यह नई दोस्ती इसी रणनीति का हिस्सा है। रिश्तों की इस नई गर्माहट को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को इसी साल कनाडा आने का आधिकारिक न्योता भी दे दिया है। कूटनीतिक गलियारों में इस प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

अयोध्या पहुंचते ही भावुक हुई एयरहोस्टेस, जमीन पर सिर रखकर किया प्रणाम- वीडियो वायरल

(जीएनएस)।

अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही एक एयरहोस्टेस ने श्री राम जन्मभूमि की दिशा में माथा टेककर अपनी आस्था दिखाई. यह भावुक पल कैमरे में कैद हुआ और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. अयोध्या एयरपोर्ट से सामने आए एक वायरल वीडियो में एक एयरहोस्टेस की श्रद्धा ने हर किसी को भावुक कर दिया. जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है और एयरहोस्टेस विमान से बाहर निकलती है, वह सीधे श्री राम जन्मभूमि की दिशा में झुककर माथा टेक देती है. यह दृश्य इतना खास है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.

वीडियो में नजर आता है कि एयरहोस्टेस जैसे ही प्लेन से नीचे उतरती है, वह कुछ कदम आगे बढ़ती

है और फिर जमीन पर सिर रखकर भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती है. वहां मौजूद लोग भी इस पल को देखकर हैरान रह जाते हैं. यह नजारा दिखाता है कि आस्था किसी भी पेशे या जगह की मोहताज नहीं होती. हालांकि एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

अयोध्या पहुंचते ही किया नमन

बताया जा रहा है कि यह वीडियो अयोध्या एयरपोर्ट का है, जहां हाल ही में यात्रियों और स्टाफ के बीच धार्मिक भावनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं. एयरहोस्टेस का यह अंदाज लोगों को इसलिए भी खास लगा क्योंकि उसने बिना किसी दिखावे के अपने विश्वास को जाहिर किया. यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने लिखा कि ह्रयही है सच्ची भक्ति.ह्व कुछ ने कहा कि ह्रदिल जीत लिया इस दृश्य ने.ह्व वहीं कुछ लोग इसे भारत की संस्कृति और आस्था की खूबसूरत झलक बता रहे हैं. तो वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर आप इतनी बड़ी भक्त हैं तो अपनी भक्ति को अपने तक रखें, कैमरे के सामने ढोंग करने से श्री राम खुश नहीं होते. वीडियो को @bhumidixit__ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

भारत के खिलाफ सीरीज के लिए आयरलैंड टीम का ऐलान, इस दिग्गज को सौंपी गई कमान

(जीएनएस)।

क्रिकेट आयरलैंड ने भारत दौरे (टी20 सीरीज) के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। बेलफास्ट में खेली जाने वाली इस दो मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले मेजबान टीम को बड़े रणनीतिक बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा है। नियमित कप्तान पॉल स्टर्लिंग के चोटिल होने के कारण स्टार टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और विकेटकीपर लॉर्कन टकर को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है।

आयरलैंड की टीम के बाहर होने वाले खिलाड़ियों और उनकी चोटों की सूची काफी लंबी है, जो टीम के संतुलन को बिगाड़ सकती है। नियमित कप्तान पॉल स्टर्लिंग पैर की मांसपेशी फटने के कारण बाहर हैं। वहीं जोश लिटिल स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण गेंदबाजी आक्रमण कमजोर नजर आ रहा है। मार्क अडायर रेक्टस मांसपेशी में खिंचाव के कारण टीम का हिस्सा नहीं

हैं। बैरी मैकार्थी और जॉर्डन नील भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं।

चोटों के इस संकट के बीच नेशनल मेंस सेलेक्टर एंड्रयू व्हाइट ने कहा कि हम इस सच को छुपा नहीं सकते कि हम चोटों से बुरी तरह घिरे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक खिलाड़ी का दुर्भाग्य दूसरे के लिए बड़ा अवसर होता है। इसी सोच के साथ हमने 14 सदस्यीय टीम में 3 नए चेहरों को शामिल किया है। टीम में शामिल होने वाले नए युवा खिलाड़ी जय मूंदड़ा, मैथ्यू हॉलार्ड और रूबेन विल्सन हैं। विल्सन ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन टी20 फॉर्मेट में वे अभी अनकैप्ड हैं।

साल 2016 में डेब्यू करने वाले और घरेलू क्रिकेट में लेइनस्टर लाइटनिंग की कप्तानी का अनुभव रखने वाले लॉरकन टकर ने जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि यह मेरे लिए बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी है। मेरा दृष्टिकोण टीम के भीतर से नेतृत्व करने और खुद उदाहरण पेश करने का है। खिलाड़ियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं और मैं ईमानदारी व सहानुभूति के साथ कप्तानी करूंगा ताकि सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें।

भारत के खिलाफ आयरलैंड की टी20 टीम

लॉरकन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गेविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदड़ा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन।

ऋषभ पंत ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी लखनऊ सुपर जाएंट्स की कप्तानी? टीम प्रबंधन के दबाव का किया जा रहा दावा

ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जाएंट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब इसे लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पंत ने फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया था।

आईपीएल 2026 का सीजन खत्म होने से पहले लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। लखनऊ के लिए यह सीजन अच्छा नहीं रहा था और टीम अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर रही थी। फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि 10 टीमों की इस प्रतियोगिता में आखिरी स्थान पर रहने के बाद स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब इस बारे में बड़ा दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंत ने अपनी मर्जी से कप्तानी नहीं छोड़ी थी।

पंत ने जब कप्तानी छोड़ी थी तो लखनऊ फ्रेंचाइजी की तरफ से बयान सामने आया था। इस बयान के अनुसार, पंत ने अपनी मर्जी से ऐसा किया। लेकिन अब रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 28 वर्षीय ऋषभ पंत ने खुद स्वेच्छा से कप्तानी नहीं छोड़ी थी, बल्कि लखनऊ मैनेजमेंट ने उन्हें पद से हटाया है। इस फैसले से आहत होकर पंत ने फ्रेंचाइजी छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि उन्हें वहां कमतर आंका जा रहा था।

इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऋषभ पंत अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौट सकते हैं। इसके लिए एक ट्रेड डील पर बात चल रही है, जिसके तहत दिल्ली के स्पिनर कुलदीप यादव लखनऊ का हिस्सा बन सकते हैं। खबरों की मानें तो पंत दिल्ली में दोबारा शामिल होने के लिए अपनी सैलरी में कटौती कराने को भी तैयार हैं, जिसके साथ उन्होंने पहले आठ सीजन बिताए हैं।

लखनऊ सुपर जाएंट्स ने आईपीएल मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम देकर खरीदा था, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। हालांकि, यह महंगी साझेदारी सिर्फ दो सीजन में ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। पंत का सफर हालांकि, लखनऊ में उतार-चढ़ाव भरा और चुनौतीपूर्ण रहा। लखनऊ लगातार तीसरे साल प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। पंत ने लखनऊ के लिए खेले 28 मैचों में 135.7 के स्ट्राइक रेट से कुल 581 रन बनाए।

150 करोड़ फीस छोड़ राजनीति में आए विजय, फिर जो हुआ उसने तमिलनाडु की राजनीति बदल दी

(जीएनएस)।

तमिल सिनेमा में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले जोसफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें दुनिया 'थलापति विजय' और उनके प्रशंसक 'इलाया थलपति' यानी युवा नेता के नाम से जानते हैं, आज सिर्फ फिल्मी दुनिया का नहीं बल्कि राजनीति का भी बड़ा नाम बन चुके हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसने दशकों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया और फिर राजनीति में कदम रखकर मुख्यमंत्री बनकर खुद को एक नए अवतार में पेश किया।

22 जून को जन्मे विजय का जन्मदिन उनके प्रशंसकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता। हर साल उनके जन्मदिन पर तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में रक्तदान शिविर, गरीबों को भोजन वितरण, छात्रों को शैक्षणिक सामग्री देने जैसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यही सामाजिक जुड़ाव आगे चलकर उनकी राजनीतिक ताकत की नींव बना।

22 जून 1974 को मद्रास (अब चेन्नई) में जन्मे विजय फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित निर्देशक रहे हैं, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक जानी-मानी प्लेबैक सिंगर हैं। सिनेमा के प्रति रुचि उन्हें विरासत में मिली और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कैमरे के सामने काम करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे वे तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार पावर में बदल गए।

विजय ने बाल कलाकार के रूप में अभिनय शुरू किया था। बतौर मुख्य अभिनेता उनकी पहली फिल्म 1992 में रिलीज हुई 'नालया थीरपू' थी। शुरूआती वर्षों में उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

1996 में आई 'पूवे उनक्कागा' ने उनके करियर की दिशा बदल दी। इसके बाद 'घिल्ली', 'पोक्किरी', 'थुप्पाकी', 'कत्थी', 'मेर्सल' और कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें तमिल सिनेमा का सबसे भरोसेमंद स्टार बना दिया। उनकी फिल्मों में एक्शन, डांस और सामाजिक संदेशों का ऐसा मिश्रण दिखाई देता था जिसने उन्हें आम लोगों से जोड़े रखा। यही वजह रही कि वे सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक जनप्रिय चेहरा बन गए।

अपने करियर के सबसे सफल दौर में विजय एक फिल्म के लिए 150 से 200 करोड़ रुपये तक फीस लेने वाले कलाकारों में गिने जाते थे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग को चौंका दिया।

उन्होंने घोषणा की कि अपनी 69वीं फिल्म 'जन नायकन' के बाद वे फिल्मों को अलविदा कह देंगे और पूरी तरह राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विजय का मानना था कि समाज के लिए बदलाव की बात सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी की जानी चाहिए।

2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (ळश्ड) की स्थापना की। पार्टी की विचारधारा को उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि विजय की लोकप्रियता वोटों में बदलेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल होगा। लेकिन उनके प्रशंसकों और जमीनी नेटवर्क ने पार्टी को शुरूआती दौर से ही मजबूत आधार देना शुरू कर दिया।

2026 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना गया। दशकों से राज्य की राजनीति मुख्य रूप से ऊ्टड और अक्अऊ्टड के इर्द-गिर्द घूमती रही थी। लेकिन विजय की पार्टी ने चुनावी मैदान में जोरदार प्रदर्शन करते हुए खुद को प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया।

सड़क पर पैदल चलना मतलब हाई रिस्क... 2019 से 2024 के बीच हादसों की इस डरावनी रिपोर्ट से समझिए

सड़कों पर गाड़ी पैदल चलने वालों की मौतें सिर्फ शहरों की समस्या नहीं हैं। 2019-24 में नेशनल हाईवे पर 30% और 50 लाख+ आबादी वाले शहरों में 12-13% मौतें हुईं। बाकी मौतें अन्य सड़कों पर हुईं। हर साल औसतन 30,500+ पैदल यात्री मौतें हुईं, जो सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः पैदल चलने वालों की मौतें सिर्फ शहरों की समस्या नहीं हैं। 2019-24 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि हाईवे और शहरों के बाहर की सड़कों पर भी ऐसी काफी मौतें हुईं। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पैदल चलने वालों की 1.8 लाख से ज्यादा मौतों में से सबसे अधिक 30% मौतें नेशनल हाईवे (ठव्) पर हुईं, जबकि 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इस दौरान ऐसी कुल मौतों का लगभग 12-13 % हिस्सा हुआ।

2019 -2024 के बीच हर साल औसतन 30500 से ज्यादा पैदल यात्री की मौत

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी मौतें उन शहरी सड़कों पर हुईं जो 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का हिस्सा नहीं हैं, और साथ ही राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों, मुख्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों जैसी अन्य श्रेणियों की सड़कों पर हुईं। राज्य पुलिस विभाग के मुताबिक 2019 और 2024 के बीच हर साल औसतन 30,500 से ज्यादा पैदल चलने वालों की मौत हुई। इससे पता चलता है कि सड़क का इस्तेमाल करने वालों में पैदल चलने वाले सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं।

54 फीसदी हादसे दो पहिया और कार से हुए

मंत्रालय की ओर से 2024 के लिए जारी सड़क दुर्घटनाओं के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 36526 दुर्घटनाओं में से लगभग 54 % दुर्घटनाएं दो-पहिया वाहनों और कारों के साथ हुईं, जिनमें 19,680 लोगों की जान चली गई। हाल के वर्षों में भी यही ट्रेंड देखा गया है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पता चलता है कि पैदल चलने वालों के लिए अलग और सुरक्षित फुटपाथ और क्रॉसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही भारत में पैदल चलने वालों की मौत का सबसे बड़ा कारण है, और यह संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है।

सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी को ध्यान देने की जरूरत

पैदल चलने वालों की मौत की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए, नीति निमार्ताओं और सड़क बनाने व रखरखाव करने वाली एजेंसियों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और सरकार को सभी सड़क उपयोगकताओं के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथ बनाने के लिए कानून बनाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पैदल चलने वालों को फुटपाथ का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है।

किस राज्य में कितनी मौतें

2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि तमिलनाडु में पैदल चलने वालों की मौत के सबसे ज्यादा मामले (4,712) दर्ज किए गए, इसके बाद बिहार (4,149), महाराष्ट्र (3,344) और पश्चिम बंगाल (3,241) का नंबर आता है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पैदल चलने वालों की मौत के 4,328 मामले दर्ज किए गए, जो इस तरह की कुल मौतों का 11.8 % था।

मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर सड़क सुरक्षा का काम देख चुके अभय दामले ने कहा कि समस्या मानकों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने में पूरी तरह से नाकाम रहना है।

साल	पैदल चलने वालों की मौतों की संख्या	नेशनल हाईवे पर	10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में
2019	25858	7749	3384
2020	23124	7753	2818
2021	29124	9462	3789
2022	32825	10160	4362
2023	35221	11180	4604
2024	36526	11386	4328

शहर की कई सड़के केवल वाहनों के लिए बनाए गए

दुर्भाग्य से, कई शहरों की सड़कें लगभग पूरी तरह से गाड़ियों के लिए बनाई गई हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों समेत पैदल चलने वालों को अपनी सुरक्षा को भारी जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ता है। हाईवे और दूसरी सड़कों पर भी पैदल चलने वालों की सुरक्षा के नियम लागू करने की जरूरत है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक दूसरे मामले में, एक 'एमिकस क्यूरी' (अदालत की मदद करने वाले वकील) ने सुझाव दिया है कि सरकार हाईवे पर पैदल चलने वालों के लिए साइनबोर्ड लगाए और पैदल चलने वालों का प्रवेश वर्जित है या पैदल चलने वालों की मनाही है जैसे साइन लगाकर उन्हें आगाह करे।

मुख्यमंत्री योगी का सख्त रुख, मथुरा में चकरोड अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। मथुरा में चकरोड पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम से जवाब तलब किया। उन्हें मौके पर जाकर कब्जा हटाने और आरोपितों पर एफआइआर कराने का आदेश दिया है।

सोमवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित जनता दर्शन हाल में मथुरा से आये एक वृद्ध ने बताया कि गांव की चकरोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है। स्थानीय स्तर पर शिकायत की गयी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर मुख्यमंत्री ने डीएम को स्वयं मौके पर जाने का निर्देश दिया।

सीएम ने कहा कि अतिक्रमण की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, विकास प्राधिकरण समेत जिम्मेदार संस्थाएं नियमित रूप से अतिक्रमण हटायें और निगरानी करते रहें।

मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों से आये प्रत्येक फरियादी से एक-एक कर मिले। प्रार्थना पत्र लिया। शिकायतों के उचित व समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। जनता दर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, बिजली के तार, पुलिस, राजस्व से जुड़े प्रार्थना पत्र आए।

मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की बातें सुनीं, फिर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने फरियादियों से कहा अभी गर्मी व धूप अधिक है। बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों से कहा कि बहुत जरूरत होने पर ही दोपहर में घर से निकलें। खानपान संयमित रखें।

शिवसेना (यूबीटी) में 6 बागी सांसद हुए शामिल, कौन हैं ये तीन संजय? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया जिक्र

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में कई दिनों से आया राजनीतिक बवंडर आखिरकार आज थम गया। 22 जून 2026 (सोमवार) को उद्धव ठाकरे शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। इस दलबदल ने न केवल उद्धव खेमे को कमजोर किया है, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा को भी एक नया मोड़ दे दिया है।

कौन हैं ये छह सांसद? शिंदे शिवसेना की बढ़ाई ताकत

शिंदे गुट में शामिल होने वाले ये सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, पाटिल-अष्टिकर और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर हैं। इन सभी सांसदों ने 17 जून को दिल्ली में आयोजित शिवसेना (यूबीटी) की संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक से दूरी बना ली थी। तभी से राजनीतिक गलियारों में इनके पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जो अब सच साबित हो चुकी हैं।

शिंदे बोले- 'सीधे 'सिक्सर' मारा, हमारे पास तीन संजय हो गए'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद इन सभी सांसदों का अपनी पार्टी में स्वागत किया और इसे अपनी ऐतिहासिक लड़ाई का अगला कदम बताया। इस मौके पर उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनके पास 'तीन संजय' आ गए हैं। शिंदे ने इस पूरे घटनाक्रम को क्रिकेट की भाषा में समझाते हुए कहा कि इस बार उन्होंने राजनीतिक पिच पर सीधे 'सिक्सर' मारा है।

कौन हैं ये तीन संजय?

ये तीन संजय उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले सांसद हैं और 2022 की अभिभाजित शिवसेना में एकनाथ के करीबी नेताओं में से थे। जिसमें संजय दीना पाटिल मुंबई नार्थ ईस्ट से, संजय उत्तमराव देशमुख वाशिम से और संजय जाधव परभनी लोकसभा सीट से सांसद हैं।

एकनाथ शिंदे ने क्यों किया इनका जिक्र?

शिंदे का यह बयान दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत पर राजनीतिक तंज था। राउत लंबे समय से शिंदे के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं। इसलिए शिंदे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उनके पास "एक नहीं, तीन-तीन संजय" हैं।

'छह टाइगर' हमारे साथ

नए सदस्यों का स्वागत करते हुए शिंदे ने उन्हें 'छह टाइगर' करार दिया जो अब उनके बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी में कोई मालिक या नौकर नहीं है, बल्कि सभी मिलकर एक समान स्तर पर काम करते हैं। शिंदे ने भरोसा दिलाया कि नए सांसदों के क्षेत्रों में लंबित पड़े सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2022 में हुई अपनी पहली बगावत का जिक्र किया

पुराने दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 में हुई अपनी पहली बगावत का जिक्र किया, जब 40 विधायकों ने उनका साथ दिया था। उन्होंने दावा किया कि वे और उनके साथी हमेशा से बालासाहेब ठाकरे की मूल विचारधारा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिंदे के अनुसार, ये सभी छह सांसद किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि 'असली शिवसेना' की नीतियों से प्रभावित होकर उनके साथ आए हैं।

बगावत के पीछे विकास क्या है वजह?

इस बड़े राजनीतिक फेरबदल के पीछे के कारणों पर जब बागी सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर से सवाल किया गया, तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। राजे निंबालकर ने विकास कार्यों को इसकी मुख्य वजह बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने वाले सांसदों को अपने क्षेत्रों के लिए पर्याप्त विकास निधि नहीं मिल पा रही थी। उनके मुताबिक, मौजूदा दौर में विकास सुनिश्चित करने के लिए सत्ता के प्रवाह के साथ चलना एक व्यावहारिक जरूरत बन गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में किसानों की होगी एंट्री, अभिजीत दीपके का बड़ा खुलासा

(जीएनएस)।

जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर आने वाले दिनों में सियासी और सामाजिक हलचल और तेज हो सकती है। आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल अभिजीत दीपके ने डल्लीक्र्ल्र्ल्र से एक्सक्लूसिव बातचीत में संकेत दिया है कि अब इस अभियान को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए विभिन्न किसान संगठनों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें भी इस मुहिम से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है।

दीपके का दावा है कि आंदोलन अब नए चरण में प्रवेश करने वाला है, जहां सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि संगठित जनदबाव बनाने पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार तक अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए कई नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिनका असर जल्द दिखाई दे सकता है।

दीपके ने बताया कि अब आंदोलन को सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए

अलग-अलग किसान संगठनों से बातचीत की जा रही है। उनका मानना है कि किसानों के कई मुद्दे मौजूदा आंदोलन की मांगों से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से उन्हें साथ लाने की कोशिश हो रही है। यदि किसान संगठन खुलकर समर्थन देते हैं तो आंदोलन का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर कई अहम बैठकों की भी योजना बनाई गई है।

अभिजीत दीपके के अनुसार आंदोलन का अगला चरण पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ाने और देश के अलग-अलग राज्यों तक पहुंच बनाने की तैयारी है। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर कैंपेन चलाए जाएंगे। दीपके का कहना है कि जब ज्यादा संगठन और लोग एक मंच पर आएंगे तो सरकार पर स्वाभाविक रूप से दबाव बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन को लेकर जनता के बीच सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल रहा है।

आगे क्या होगा? दीपके ने दिए संकेत

मीडिया से बातचीत में दीपके ने आगे की रणनीति के कई संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का ऐलान किया जाएगा। आंदोलन को लंबी लड़ाई मानते हुए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की योजना बनाई गई है। उन्होंने समर्थकों से जुड़े रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। दीपके का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इसी दौरान आंदोलन के विस्तार और नए सहयोगियों की तस्वीर साफ हो सकती है।

जंतर-मंतर पर कॉकरोच विवाद ने क्यों पकड़ा तूल?

अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच मिलने की घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खूब चर्चा हुई। उनका कहना है कि कुछ लोग इस मुद्दे को आंदोलन से जोड़कर माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि प्रदर्शन का फोकस अपने मुख्य मुद्दों पर ही रहेगा। दीपके के मुताबिक ऐसी घटनाएं आंदोलन की दिशा तय नहीं करतीं और इससे लोगों का समर्थन कम होने वाला नहीं है।

नीट परीक्षा में 45 हजार छात्रों को सहारा, फ्री बस, कूलिंग जोन से अभिभावक खुश, सीएम रेखा गुप्ता की हुई तारीफ

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के दिन दिल्ली सरकार की एक खास पहल ने हजारों छात्रों और उनके परिवारों का तनाव काफी हद तक कम कर दिया। भीषण गर्मी के बीच राजधानी के 97 परीक्षा केंद्रों पर बनाए गए विशेष कूलिंग जोन और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा ने परीक्षा देने पहुंचे 45 हजार से अधिक छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी।

यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर परीक्षा केंद्रों के बाहर तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस पहल की चर्चा होती रही आमतौर पर परीक्षा के दौरान सारी व्यवस्था सिर्फ उम्मीदवारों पर केंद्रित रहती है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने अभिभावकों को भी ध्यान में रखा।

सभी 97 परीक्षा केंद्रों के बाहर जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन बनाए गए, जहां माता-पिता और परिवार के सदस्य आराम से इंतजार कर सकें।

करीब 2500 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाए गए इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी,

ओआरएस, चाय और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गर्मी और उमस के बीच यह व्यवस्था अभिभावकों के लिए किसी राहत शिविर से कम नहीं रही।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परीक्षा से पहले घोषणा की थी कि ठएएळ उम्मीदवार 21 जून को दिल्ली परिवहन निगम (ऊळउ) की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को केवल अपना वैध ठएएळ एडमिट कार्ड दिखाना था। सरकार का मानना था कि परीक्षा वाले दिन ट्रैफिक और परिवहन की परेशानियां छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में मुफ्त यात्रा की सुविधा ने न सिर्फ आर्थिक राहत दी बल्कि समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में भी मदद की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था हर छात्र के सपनों और हर अभिभावक की उम्मीदों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों की सफलता की कामना कर रही है। रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षा आयोजित कराना नहीं, बल्कि छात्रों और उनके परिवारों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है ताकि वे बिना तनाव के परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर सकें।

दिल्ली सरकार की यह पहल केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक मानवीय सोच का उदाहरण भी मानी जा रही है। जहां एक तरफ छात्र परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों को भीषण गर्मी में घंटों खड़े रहने से राहत मिली। फ्री बस यात्रा और कूलिंग जोन की व्यवस्था ने यह संदेश दिया कि परीक्षा सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे परिवार की चुनौती होती है।

15 छात्रों की मौत के जिम्मेदार 16 आरोपी कौन? अफसरों का घालमेल! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- कोई नहीं बचेगा

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार (22 जून 2026) दोपहर एक तीन मंजिला इमारत ने आग का भयानक रूप ले लिया। अलीगंज के पुरनिया/सेक्टर डी इलाके में नीचे पेट शॉप और क्लिनिक, ऊपर दूसरी मंजिल पर लर्निंग स्पेस कोचिंग-लाइब्रेरी और Head Hopper Studio (3D आर्ट प्रोडक्शन एवं गेम एसेट आउटसोर्सिंग) चल रहे था। दोपहर करीब 3 बजे ग्राउंड फ्लोर की Drools Aliganj Pet Shop या आसपास शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग तेजी से ऊपर फैली। धुएं ने पूरी मंजिल को घेर लिया। इमरजेंसी एग्जिट न होने और सिंगल एंट्री-एग्जिट के कारण छात्र बाहर नहीं निकल पाए।

इस हादसे में 15 युवा छात्रों और प्रोफेशनल्स की मौत हो गई। अधिकांश मौतें दम घुटने से हुईं। यह लखनऊ का अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड बन गया है। लेकिन यह महज हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्थागत लापरवाही, अवैध निर्माण और अफसर-बिल्डर मिलीभगत का नतीजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जिम्मेदार किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आइए विस्तार से जानें कहां- कहां चूक और खामियां? किसकी गलती?

CM योगी का सख्त रुख और मुआवजे की घोषणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल और ङ्क्रह्रव ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और घायलों का हाल जाना। योगी ने घोषणा की कि

प्रत्येक मृतक परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता। प्रत्येक घायल को 50 हजार रुपये।

पीएम मोदी ने PMNRF से अतिरिक्त 2 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की।

योगी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले ही मौके पर पहुंचकर भावुक हो गए थे।

अब बात करते हैं किसने इन छात्रों को आग में झोंका?

16 आरोपी कौन? रामेश्वरम ग्रुप और अफसरों का तगड़ा कनेक्शन

जांच एजेंसियों ने 16 लोगों की प्रारंभिक लिस्ट तैयार कर ली है। इनमें बिल्डर और तत्कालीन अधिकारी-इंजीनियर दोनों शामिल हैं।

मुख्य आरोपी (बिल्डर):

वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (-रामेश्वरम ग्रुप के मालिक, RITM कॉलेज संचालक, सीतापुर रोड, गोविंदपुरम)।

सुरेंद्र प्रताप शुक्ला

धीरेंद्र प्रताप शुक्ला

इमारत वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर बनी। नक्शा उनके और परिवार के सदस्यों के नाम से आवासीय पास हुआ था। लेकिन 2014 में बिना अनुमति कमर्शियल उपयोग शुरू कर दिया गया। यहां पेट शॉप, क्लिनिक, कोचिंग और 3ऊस्टूडियो चल रहे थे। नगर निगम 2022 से कमर्शियल टैक्स वसूल रहा था, यानी अवैध बदलाव की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।

अफसरों पर आरोप क्या-क्या?

नक्शा पास करने वाले तत्कालीन इंजीनियर और अधिकारी।

फायर NOC और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट न देने/न लेने वाले।

विद्युत विभाग के अधिकारी (20 kW लोड पास था, 35.50 kW उपयोग हो रहा था)।

LDA (लखनऊ विकास प्राधिकरण) और नगर निगम के इंस्पेक्शन अधिकारी।

अन्य विभागों के कर्मचारी, जिन्होंने सालों तक अनदेखी की।

कुल 16 आरोपी। इनमें से कई तत्कालीन अफसर शामिल हैं। शुरूआती जांच में साफ हुआ कि इमारत पर फायर NOC, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं था। फिर भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं।

शुरूआती जांच के अनुसार आग अउ शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन असली वजह सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी थी।

कोचिंग हब अलीगंज की पुरानी समस्या

अलीगंज लखनऊ का बड़ा कोचिंग केंद्र है। JEE, NEET, स्किल कोर्सेस और 3D-गेमिंग ट्रेनिंग यहां आम हैं। लेकिन ज्यादातर संस्थान सिंगल एंट्री-एग्जिट वाले पुराने भवनों में चल रहे हैं। व्यावसायिक भवनों में पेट शॉप, क्लिनिक और कोचिंग का मिश्रण आग फैलने का खतरा बढ़ाता है। फायर नॉर्म्स का पालन नहीं करना यहां आम बात बन गई थी।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, याचिका पर नियमित प्रक्रिया से होगी सुनवाई

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः राम मंदिर में चढ़ावे के लेकर की गई हेरा-फेरी का विवाद तूल पकड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार रक्ळ जांच करवा रही है। तो दूसरी तरफ चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में तत्काल सुनवाई की जरूरत बताते हुए सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट की मांग की गई थी।

राम मंदिर चूंकि देश के तमाम भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए यहां भक्तों के चढ़ावे में तथाकथित रुप से हेरा फेरी की बात भक्तों को व्यथित कर रही है। इस सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई थी कि तत्काल इस मामले पर सुनवाई करे। लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में इस मामले को तत्काल या आउट ऑफ टर्न सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

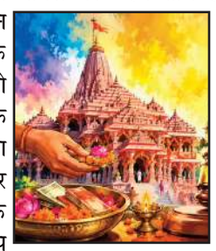

हाईकोर्ट में यह याचिका मोहित अशोक की ओर डाली गई है। उन्होंने हाईकोर्ट से घटना की गंभीरता बताते हुए पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मंदिर को मिले सभी दान और चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी मांग की गई है।

इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी भी मामले को आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई के लिए स्वीकार करने के लिए विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अदालत ने साफ किया कि फिलहाल राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (रक्ळ का गठन किया है। और रक्ळ की जांच लगभग पूरी हो गई है। और इसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर ही बनाया है जिससे तथ्यों की सही जांच हो सके और फैल रही भ्रामक सूचनाओं की सच्चाई सामने आए।

और फिर अदालत ने फिलहाल याचिका को नियमित सूची के अनुसार सुनवाई के लिए रखने का निर्णय लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोर्ट ने याचिका की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि केवल सुनवाई के समय और प्रक्रिया से जुड़ा निर्णय दिया है।